नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 208
दि. 02.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत, संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया

नई दिल्ली में देश की न्यायिक और राजनीतिक हलचलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कथित नफरती भाषण मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपलब्ध सामग्री और भाषणों के परीक्षण के आधार पर उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। यह फैसला 29 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ द्वारा सुनाया गया, जिसने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को एक महत्वपूर्ण कानूनी दिशा प्रदान की है।

यह मामला वर्ष 2020 में शाहीन बाग में हुए एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिए गए कथित भाषणों से जुड़ा हुआ था। उस समय देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर व्यापक विरोध हो रहा था और शाहीन बाग इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी दौरान भाजपा नेताओं के कुछ बयान सामने आए, जिन पर विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले थे। इन आरोपों के आधार पर बृंदा करात और के.एम. तिवारी जैसे नेताओं ने शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की गहराई से समीक्षा की और यह पाया कि भाषणों में ऐसा कोई स्पष्ट तत्व मौजूद नहीं है, जो सीधे तौर पर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा या सार्वजनिक अशांति को भड़काता हो। अदालत ने कहा कि किसी भी भाषण को आपराधिक श्रेणी में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें स्पष्ट रूप से उकसावे या हिंसा का आह्वान हो, जो इस मामले में पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं होता। इसी आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन बयानों के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता।

हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर भी स्पष्टता दी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्व सरकारी अनुमति या सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह अनुमति केवल उस चरण में जरूरी होती है, जब अदालत मामले का संज्ञान लेने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच शुरू करने से पहले ही सैंक्शन को अनिवार्य बना दिया जाए, तो इससे जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने जांच प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

हालांकि अदालत ने आरोपित नेताओं को राहत दी, लेकिन हेट स्पीच को लेकर अपनी चिंता भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरती भाषण संविधान में निहित भाईचारे और सामाजिक सद्भावना की भावना के खिलाफ हैं। ऐसे बयान समाज की नैतिक संरचना को कमजोर करते हैं और दीर्घकालिक रूप से सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बावजूद अदालत का मानना है कि वर्तमान में मौजूद कानूनी ढांचा इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है और इसके लिए नए कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।

यह मामला पहले निचली अदालतों में भी विचाराधीन रहा था। अगस्त 2020 में ट्रायल कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। इसके बाद 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा निर्णय ने इन सभी निष्कर्षों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे यह मामला न्यायिक रूप से समाप्त हो गया है।

राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर जहां भाजपा इसे अपने नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्ति के रूप में देख रही है, वहीं विपक्षी दलों के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, इस निर्णय ने एक व्यापक बहस को भी जन्म दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नफरती भाषण के बीच की रेखा कहां खींची जानी चाहिए। यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना इस मामले के शुरू होने के समय था।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि न्यायपालिका किस प्रकार संवेदनशील और विवादास्पद मामलों में संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक ओर जहां वह कानून के दायरे में रहकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, वहीं दूसरी ओर समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता को भी नजरअंदाज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी संतुलन का एक उदाहरण है, जहां अदालत ने तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेते हुए व्यापक सामाजिक संदेश भी देने का प्रयास किया है।

अंततः, यह फैसला केवल दो नेताओं को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय प्रणाली के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें हर मामले को उसके तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर परखा जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी आरोप को सिद्ध करने के लिए केवल भावनात्मक या राजनीतिक आधार पर्याप्त नहीं होते, बल्कि ठोस प्रमाण और कानूनी कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक होता है। आने वाले समय में यह निर्णय न केवल हेट स्पीच से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में काम करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए।

तुमकुरु में बर्ड फ्लू का खतरा: 44 मोरों की मौत से हड़कंप, H5N1 की पुष्टि के बाद प्रशासन

कर्नाटक के तुमकुरु जिले से सामने आई एक गंभीर घटना ने वन्यजीव संरक्षण और जनस्वास्थ्य दोनों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यहां एक सप्ताह के भीतर 44 मोरों की रहस्यमय मौत ने प्रशासन को सतर्क कर दिया, और अब जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि इन पक्षियों की मौत का कारण खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं और संबंधित विभाग मिलकर संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश में जुट गए हैं।

यह मामला सबसे पहले 16 अप्रैल को सामने आया, जब तुमकुरु तालुका के विभिन्न इलाकों में मोरों के मृत पाए जाने की खबर आई। शुरुआत में इन मौतों को सामान्य या प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखा गया, लेकिन जैसे-जैसे संख्या बढ़ती गई, मामला गंभीर होता चला गया। एक सप्ताह के भीतर केसरामाडु, हिरेहल्लि और गुलूर ग्राम पंचायतों के खेतों में बड़ी संख्या में मोरों के शव मिलने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया और सभी मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इन सैंपलों को आईसीएआर-नेशनल

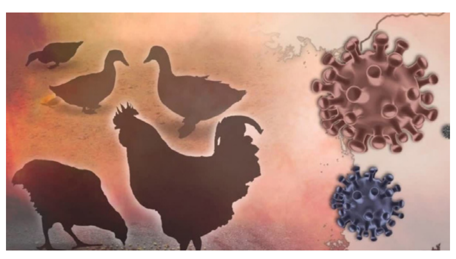

इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस, भोपाल भेजा गया, जहां विस्तृत परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी पक्षी H5N1 वायरस से संक्रमित थे। यह वायरस बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक रूप माना जाता है, जो पक्षियों में तेजी से फैलता है और बड़े पैमाने पर मौत का कारण बन सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 23 अप्रैल के बाद से इस क्षेत्र में कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

घटना की पुष्टि होते ही प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए। प्रभावित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्मों को अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें सख्त निगरानी में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या पक्षियों में असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

वन्यजीव विभाग के मुख्य वन संरक्षक कुमार पुष्कर के अनुसार, इस संकट से निपटने के लिए वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग मिलकर समन्वित रूप से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि संक्रमण आगे न फैले और मानव आबादी तक इसका कोई खतरा न पहुंचे। इसके लिए सभी स्तरों पर निगरानी और रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों पर विशेष नजर रखें। यदि किसी व्यक्ति में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत जांच और आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीई किट, ट्रिपल-लेयर मास्क, ओसेल्टामिविर दवा, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम और थ्रोट स्वैब किट का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि H5N1 वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन कुछ मामलों में यह इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, खासकर तब जब संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने की संभावना अधिक हो। हालांकि ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं, फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी मृत या बीमार पक्षी को छूने से बचें और तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वन्यजीवों में फैलने वाली बीमारियां किस तरह से व्यापक खतरा बन सकती हैं। मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी इतनी बड़ी संख्या में मौत न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से चिंता का विषय है, बल्कि यह संकेत भी है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं न कहीं असंतुलन पैदा हो रहा है।

बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश धांधली की शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त

कोलकाता से आई ताजा खबर ने पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मिली गड़बड़ियों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है। आयोग का यह फैसला 2 मई को लागू होगा और इसे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी सामान्य शिकायत के आधार पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर प्राप्त विस्तृत रिपोर्टों और गहन जांच के बाद लिया गया है। जिन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा, वे सभी दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आते हैं। यह वही जिला है, जहां चुनाव के दौरान कई स्थानों से अनियमितताओं और धांधली की शिकायतें सामने आई थीं। जांच के दौरान इन शिकायतों की पुष्टि होने के बाद ही आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है।

सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, जहां 11 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ भी पुनर्मतदान

की सूची में शामिल किए गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों से भारी संख्या में शिकायतें मिली थीं, जिनमें मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी, मतदाताओं को प्रभावित करने और नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल थे।

निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग का मानना है कि यदि किसी भी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में खामियां पाई जाती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पुनर्मतदान जैसे कठोर कदम उठाने में भी आयोग पीछे नहीं हट रहा है।

इस निर्णय के साथ ही आयोग ने यह संकेत भी दिया है कि अन्य संदिग्ध क्षेत्रों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद यह तय होगा कि वहां भी किसी बूथ पर पुनर्मतदान की आवश्यकता है या नहीं। अधिकारियों के अनुसार, फाल्टा से रिपोर्ट मिलते ही उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तर पर तैनात चुनाव आयोग की टीमें लगातार हर छोटी-बड़ी रिपोर्ट की निगरानी कर रही हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है और उसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा रही है। आयोग का यह रुख साफ दर्शाता है कि वह चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर विपक्षी दल लंबे समय से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं, वहीं सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा पुनर्मतदान का आदेश देना इस बात का संकेत है कि शिकायतों में कुछ न कुछ दम जरूर पाया गया है।

हालांकि, इस फैसले से राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा सकता है, क्योंकि पुनर्मतदान का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। जिन क्षेत्रों में दोबारा वोटिंग हो रही है, वहां सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

अंततः, यह पूरा घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक होता है। यदि उस विश्वास पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें दूर करना जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग का यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वोट की कीमत बनी रहे और जनता का विश्वास कायम रहे। अब देखना यह होगा कि 2 मई को होने वाला पुनर्मतदान कितनी शांति और निष्पक्षता के साथ संपन्न होता है और इसका अंतिम परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है।

मतदान के बाद बंगाल में हिंसा की आग: तीन जिलों में हमले, आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस की कार्रवाई तेज

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान के बाद लोकतंत्र का उत्सव अचानक तनाव और हिंसा की घटनाओं से दागदार हो गया। मतदाताओं की भारी भागीदारी के बाद जहां शांतिपूर्ण परिणाम की उम्मीद की जा रही थी, वहीं राज्य के तीन जिलों में भड़की राजनीतिक हिंसा ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। अलग-अलग घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षाबलों ने चार मई तक पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी है, जिससे कई संवेदनशील इलाके छावनी जैसे नजर आने लगे हैं।

मुर्शिदाबाद जिले में हुई घटना ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के लोचनपुर गांव में गुरुवार रात अचानक हिंसा भड़क उठी। यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिंग एजेंट रूहूल अमीन पर जानलेवा हमला किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अमीन एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोगों का समूह वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। आरोप लगाया गया है कि इस हमले का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी ने किया। परिजनों का कहना है कि अमीन को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

इस घटना को लेकर विवाद उस समय और गहरा गया, जब सीपीआई(एम) ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाद में जब रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल का दौरा

किया गया। मामले में एक और गंभीर आरोप यह सामने आया है कि चाय की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का कुछ फुटेज डिलीट कर दिया गया है, जिससे घटना की सच्चाई सामने आने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पुलिस ने इस पहलू को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। दूसरी बड़ी घटना मालदा जिले के रतुआ क्षेत्र के उत्तर बालूपुर में सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महानंदा मंडल पर हमला किया गया। गुरुवार दोपहर हुई इस घटना में आरोप है कि कुछ लोगों ने मंडल को बीच सड़क पर रोक लिया और उन पर ईंटों से हमला कर दिया। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत को लेकर डॉक्टरों की निगरानी जारी है।

भाजपा नेताओं ने इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया है। वरिष्ठ नेता खगेन मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर घायल नेता का हालचाल जाना और आरोप लगाया कि मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण हिंसा नहीं हो सकी, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बताया है।

तीसरी घटना उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज थाना क्षेत्र के दुलदुली काकपाड़ा गांव में सामने आई, जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। यह झड़प इतनी उग्र थी कि इसमें पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव था, जो चुनाव के बाद हिंसक रूप ले बैठा।

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक भाजपा समर्थक और एक तृणमूल समर्थक शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह संघर्ष राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इलाके में लगातार गश्त की जा रही है, ताकि आगे किसी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके। इन तीनों घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद भी राजनीतिक तनाव समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कई जगहों पर यह और अधिक उग्र हो गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों।

राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हर पक्ष दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। जहां एक ओर विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दे रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने आम जनता के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद इस तरह की हिंसा लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के बाद शांति बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि मतदान के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर हर संवेदनशील इलाके पर बनी हुई है। जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और हालात को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सख्ती लंबे समय तक शांति बनाए रख पाएगी या फिर राजनीतिक टकराव आगे भी इसी तरह हिंसा का रूप लेता रहेगा। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब तय करेंगे, लेकिन फिलहाल बंगाल में हालात पूरी तरह सतर्कता और तनाव के बीच बने हुए हैं।

संपादकीय

मौत की राह बनती सड़कों पर हो अनुशासन

देश के नीति-नियंताओं की सोच रही है कि विकास के लिए चौड़ी व रफ्तार वाली सड़कें जीवन रेखा का काम करें। हाल के वर्षों में इसी सोच के साथ राजग सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया। देश के उत्थान के लिए विकास के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। लेकिन विकास की इस उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विसंगति भी सामने आई कि इन पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि उच्च तकनीक से तैयार आकर्षक व सुविधाजनक एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। यूं तो देश की कुल सड़कों में दो फीसदी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इनकी संख्या तीस फीसदी हो गई है। जो हमारी गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की इस गहरी चिंता को महसूस करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस संकट पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार तथा इससे संबधित विभागों को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रही है अधिकारियों की उदासीनता व निर्माण से जुड़ी खामियों की वजह से राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे दुर्घटना के कारक नहीं बनने चाहिए। इस दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मार्ग खतरे का गलियारा न बने। विडंबना यह भी है कि देश में आम लोगों में ट्रैफिक से जुड़ी अनुशासन की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। खुली सड़क मिलते ही रफ्तार तेज होने लगती है, यह जानते हुए कि ये गति हमारी दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा तेज स्पीड में भी फोन पर बात करते रहना और शराब पीकर वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ है।

यह विडंबना ही है कि भारत में दुनिया के अन्य विकसित व समकक्ष विकासशील देशों के अनुपात में वाहनों की संख्या तो कम है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हम अव्वल हैं। यह आंकड़ा डराता है कि साल भर में होने वाली करीब साढ़े चार लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लाखों लोग घायल होते हैं। दुर्भाग्य से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवनपर्यंत अपंगता का शिकार हो जाते हैं। विडंबना यह भी कि सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ने वाले लोगों में बड़ी संख्या युवा आबादी की है। ये युवा आबादी अपने परिवार की कमाई का मुख्य जरिया होती है, उनकी मौत पूरे परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल देती है। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। वास्तव में कोशिश होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होने वाले प्रयास जमीनी हकीकत भी बनें, जो वास्तव में राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे को दुर्घटनाओं से निरापद बना सकें। निस्संदेह, चौड़ी व तेज गति देने वाली सड़कें देश के विकास को प्राणवायु देती हैं, लेकिन ये सड़कें यात्रियों की प्राण रक्षा करने वाली भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि राजमार्गों पर ढाबे एक निश्चित दूरी पर हों और उनके पास ट्रकों व भारी वाहनों को खड़ा करने का पर्याप्त स्थान हो। साथ ही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनने वाले सड़क पर खड़े वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बने और सख्त जुर्माना तय हो। कायदे से राजमार्गों पर कहीं भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण में किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे, इसके लिये भी पर्याप्त सतर्कता उपाय किए जाने चाहिए। इन मार्गों पर अंधेरे में भी नजर आने वाले पर्याप्त संकेतक होने चाहिए ताकि वाहन चालकों को किसी तरह का असमंजस राजमार्ग पर चलते हुए न हो। वक्त आ गया है कि देश में दुर्घटनाओं को टालने के लिए आधुनिक यातायात प्रणाली के अनुसंधान व प्रयोग की दिशा में काम किया जाए।

Great Nicobar Project राष्ट्रहित में है, इसका विरोध करना China का खुलकर समर्थन करने जैसा है

> ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर छिड़ी बहस के बीच, इसे हिंद महासागर में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का मुकाबला करने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मलक्का जलडमरूमध्य पर भारत की यह सामरिक बढ़त देश के आर्थिक और रणनीतिक भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना को लेकर देश में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना को देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध और घोटाला बताया है। उन्होंने अपने दौरे के बाद कहा कि यहां के घने जंगल, जो सदियों में विकसित हुए हैं, अब बड़े पैमाने पर काटे जाने के खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन क्षेत्र को समाप्त किया जाएगा और लाखों पेड़ों की कटाई होगी, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। राहुल गांधी ने इसे विकास के नाम पर विनाश बताया और कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उनका आरोप है कि स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना उनकी जमीन और संसाधनों को छीना जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की ओर से पहले भी इस परियोजना को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसमें इसे शोंपेन जनजाति और द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बताया गया। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए समाचार-पत्रों में एक विस्तृत लेख लिखा था।दूसरी ओर, इस परियोजना को देश की सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति आयोग द्वारा तैयार और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना की लागत लगभग 81000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें चार प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें एक विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऊर्जा संयंत्र और सैन्य ढांचे का विस्तार शामिल है। हम आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। यह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। चीन का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात और उसका बड़ा व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में

इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति उसे सामरिक बढ़त दिला सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि गैलेथिया खाड़ी में बनने वाला बंदरगाह भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में नई पहचान दिला सकता है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का लगभग 25 प्रतिशत माल विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से स्थानांतरित होता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इस परियोजना के पूरा होने पर भारत इस निर्भरता को समाप्त कर सकता है और अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत कर सकता है।

चीन की रणनीति को देखते हुए यह परियोजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दो दशकों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाह विकसित किए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और म्यांमार का क्याउकफ्यू शामिल हैं। इनका उद्देश्य समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाना और भारत को घेरना है।

इसके जवाब में भारत ने भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समुद्री रणनीति विकसित की है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। इसमें ओमान, इंडोनेशिया और सेशेल्स जैसे देशों में बंदरगाहों तक पहुंच और सैन्य सहयोग शामिल है। ग्रेट निकोबार इस रणनीति का केंद्र बिंदु माना जा रहा है।

इसके अलावा, हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के उपयोग से वैश्विक तेल आपूर्ति पर प्रभाव डालने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किसी भी देश के लिए कितना शक्तिशाली साधन हो सकता है। इस स्थिति में यदि भारत मलक्का जलडमरूमध्य के पास अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो यह उसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बना सकता है।

मोदी सरकार का कहना है कि परियोजना को पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा मानकों के तहत स्वीकृति दी गई है। शोंपेन जनजाति की सुरक्षा के लिए विशेष नीतियां, निगरानी तंत्र और अन्य उपाय लागू किए गए हैं। सरकार के अनुसार परियोजना द्वीप के कुल क्षेत्रफल के सीमित हिस्से पर ही आधारित है और विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। कुछ विदेशी संगठनों ने इसे जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। लेकिन इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि चीन के समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की यह परियोजना साकार रूप ले सके।

उधर, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इस पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने विभिन्न साक्षात्कारों और समाचारपत्रों में अपने आलेखों के जरिये इस परियोजना की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष के नेता ने हाल में इस द्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना को इकोलॉजी और पर्यावरण के विनाश का कारण बताते हुए एक बड़ा घोटाला और 'राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ अपराध' करार दिया। उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की रणनीतिक दिशा की बात हो, तो तस्वीर का केवल एक हिस्सा देखना उचित नहीं लगता। यह परियोजना देश के भविष्य की एक सख्त सामरिक और आर्थिक आवश्यकता है।

आर.के.एस. भदौरिया लिखते हैं कि भारत लंबे समय तक अपनी सुरक्षा सोच में भूमि-सीमाओं पर अधिक केंद्रित रहा। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक शक्ति का केंद्र है। ग्रेट निकोबार का भूगोल अपने आप में भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और स्टेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 30% कंटेनर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने कॅरियर में कई बार महसूस किया कि जब आपकी निगरानी की क्षमता सीमित होती है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आपके पास अग्रिम मोर्चे पर ठोस ढांचा हो यानि हवाई पट्टी, बंदरगाह, संचार प्रणाली आदि हो तो आप स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाते है।

उन्होंने लिखा है कि ग्रेट निकोबार को अनसिंकेबल एअरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समुद्र के बीच एक ऐसा स्थायी ठिकाना होगा, जो किसी जहाज की तरह डूब नहीं सकता, लेकिन उसकी तरह काम कर सकता है। यहां से वायुसेना के विमान उड़ सकते हैं, नौसेना के जहाज संचालन कर सकते है और तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त रणनीति बना सकती है। अंडमान और निकोबार में पहले से ही त्रि-सेवा कमान है, लेकिन उसे आधुनिक और व्यापक ढांचे की जरूरत लंबे समय से महसूम की जा रही थी। उन्होंने लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे बड़े भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन का 60% से 75% ऊर्जा व तेल आयात इसी मलक्का कॉरिडोर से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा है कि बीजिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते है, जिसे वे 'मलक्का डिलेमा' कहते है। चीन दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हंबनटोटा और म्यामार के क्याउकफ्यू बंदरगाह में अपने सैन्य और दोहरे उपयोग वाले बेस बनाकर हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह थाईलैंड में 'क्रा कैनाल' बनाने की फिराक में है ताकि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सीधे हिंद महासागर में प्रवेश कर सके।

प्रेरणा

अडिग श्रद्धा का रहस्य और धर्म की वास्तविक अनुभूति

धर्म को अक्सर लोग बाहरी क्रियाओं, पूजा-पाठ, व्रत और अनुष्ठानों तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और सूक्ष्म है। धर्म का वास्तविक आधार मनुष्य के भीतर स्थित वह अदृश्य शक्ति है जिसे श्रद्धा कहा जाता है। यह श्रद्धा ही है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है, उसे परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव में भी स्थिर बनाए रखती है और अंततः उसे उस सत्य तक पहुँचाती है, जिसे धर्मतत्व कहा गया है। यदि यह श्रद्धा डगमगा जाए, तो सबसे बड़ा ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है, और यदि यह अडिग बनी रहे, तो साधारण व्यक्ति भी उच्चतम आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकता है।

प्राचीन भारतीय परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक कथा मिलती है, जिसमें शुकदेव ने अपने पिता और गुरु व्यास से धर्म के गूढ़ तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। शुकदेव स्वयं अत्यंत ज्ञानी और वैराग्य से युक्त थे, फिर भी उन्होंने यह समझा कि केवल शास्त्रों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धर्म का वास्तविक अनुभव जीवन की परीक्षा और आंतरिक स्थिरता से प्राप्त होता है। उनकी जिज्ञासा को देखकर व्यास ने उन्हें सीधे उत्तर देने के बजाय राजा जनक के पास जाने का निर्देश दिया। यह निर्देश अपने आप में एक गहरा संदेश था कि धर्मतत्व को समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और धैर्य की आवश्यकता होती है। शुकदेव राजा जनक के पास पहुँचे और अपने आगमन की सूचना दी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक मिलने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उन्हें तुरंत भेंट का अवसर नहीं मिला। उत्तर मिला कि उन्हें सात दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही राजा उनसे मिलेंगे। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए असहज हो सकती थी। कोई इसे अपमान मान सकता था, कोई इसे अनदेखी समझकर लौट सकता था, और कोई क्रोध में प्रतिक्रिया दे सकता था। लेकिन शुकदेव ने इन सब भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार किया और शांत मन से प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उन सात दिनों के दौरान शुकदेव को न तो विशेष आतिथ्य मिला, न ही कोई आरामदायक व्यवस्था। वे जहाँ-तहाँ ठहरते रहे, कभी खुले आकाश के नीचे, कभी किसी पेड़ की छाया में। बाहरी दृष्टि से यह स्थिति कष्टदायक थी, लेकिन उनके भीतर की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इन परिस्थितियों को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। वे लगातार यह विचार करते रहे कि यदि उद्देश्य महान है, तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ भी उसी का हिस्सा हैं। समय का विलंब, परिस्थितियों की कठोरता और बाहरी असुविधाएँ—ये सब केवल उस आंतरिक शक्ति को परखने के साधन हैं, जिसे श्रद्धा कहा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि श्रद्धा केवल तब तक सच्ची नहीं मानी जाती जब तक सब कुछ अनुकूल हो। वास्तविक श्रद्धा वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग बनी रहे। जब मनुष्य को सम्मान मिले, सुविधा मिले, और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, तब श्रद्धा बनाए रखना आसान होता है। लेकिन जब उसे उपेक्षा, विलंब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब उसकी श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा होती है। शुकदेव ने इस परीक्षा को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ पार किया।

सात दिन पूरे होने के बाद अंततः उन्हें राजा जनक के दरबार में बुलाया गया। इस बार उनका स्वागत अत्यंत सम्मान के साथ किया गया। उन्हें उचित आसन दिया गया, आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया गया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। यह परिवर्तन केवल बाहरी व्यवहार का नहीं था, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि शुकदेव ने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, जो उनकी श्रद्धा की दृढ़ता को परखने के लिए ली गई थी। जब उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया और वे वापस जाने लगे, तब राजा जनक ने उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की श्रद्धा की तीव्रता और स्थिरता ही यह निर्धारित करती है कि वह धर्मतत्व को प्राप्त करेगा या नहीं। यदि श्रद्धा में शिथिलता आ जाए, तो साधक मार्ग से भटक जाता है; और यदि श्रद्धा अडिग बनी रहे, तो वह अंततः सत्य को प्राप्त कर लेता है। यही वह मूल सिद्धांत है, जो धर्म के सार को स्पष्ट करता है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज का मनुष्य भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करता है। वह सफलता चाहता है, शांति चाहता है, और अपने जीवन में अर्थपूर्णता की खोज करता है। लेकिन जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तो वह निराश हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या अपने प्रयासों को छोड़ देता है। ऐसे समय में यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं और हमारी श्रद्धा अडिग है, तो हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक और समझपूर्ण विश्वास है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। यह हमें यह सिखाती है कि हर विलंब, हर कठिनाई और हर परीक्षा हमारे भीतर की क्षमता को निखारने का एक अवसर है। जब हम इन अवसरों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरा परिवर्तन अनुभव करते हैं।

धर्मतत्व की प्राप्ति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति है। यह तब संभव होती है जब मनुष्य अपने भीतर की अशांति, संदेह और अस्थिरता को पार कर लेता है और एक ऐसी अवस्था में पहुँचता है, जहाँ वह पूर्णतः संतुलित और शांत हो जाता है। यह अवस्था ही वास्तविक सुख और संतोष का स्रोत है। इसे ही हमारे शास्त्रों में अमृतत्व कहा गया है—एक ऐसी स्थिति, जहाँ मनुष्य जीवन के उतार-चढ़ाव से ऊपर उठकर स्थायी शांति को प्राप्त करता है।

अंततः, शुकदेव और राजा जनक का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान या प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक है एक अटूट श्रद्धा, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखे। जब यह श्रद्धा हमारे भीतर जागृत हो जाती है, तब हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च अर्थ और उद्देश्य से भर देते हैं। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है और यही वह मार्ग है, जो हमें आत्मतत्व की ओर ले जाता है।

ऊर्जा-आत्मनिर्भरता की राह में बड़ा कदम

भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हाल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने 6 अप्रैल को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम 'क्रिटिकैलिटी' प्राप्त की, जो नाभिकीय चेन रिएक्शन की शुरुआत है। यह प्रोटोटाइप एफबीआर 500 मेगावाट विद्युत (एमडब्ल्यूई) रिएक्टर है, जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) ने तमिलनाडु के कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में निर्मित किया है।

यह तकनीक नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम पर निर्भरता कम करेगी। इस उपलब्धि के साथ, भारत अपने तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है, जिसकी परिकल्पना डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने की थी। वैश्विक स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण परिघटना है। इसके पूर्ण संचालन में आने के बाद, रूस के बाद भारत, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करने वाला, दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा।

ईरान-युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभावों के साथ, दुनियाभर के देश ऊर्जा सुरक्षा की तलाश में हैं। ज्यादातर देश कोयले और पेट्रोलियम के रूप में फॉसिल फ्यूल के सहारे हैं, पर अब उनके खत्म होने का समय है। वैसे भी उनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को देखते हुए विकल्पों की तलाश चल रही है। पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा सबसे आगे है, क्योंकि बड़े स्तर पर वही जरूरत पूरी कर सकती है। उसके साथ भविष्य के तकनीकी विकास भी जुड़े हैं, जो नए विकल्पों को खोलेंगे।

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल में संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त घोषणा की है। व्यावसायिक रूप से इस पद्धति से बिजली बनाने में अभी कई दशक लगेंगे, पर भविष्य में यह ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत साबित होगा। यह बिजली भी परमाणु के नाभिकीय में छिपे ऊर्जा स्रोत पर आधारित होगी, पर अभी प्रचलित विखंडन पर आधारित नाभिकीय ऊर्जा से एकदम अलग और सुरक्षित होगी।

नाभिकीय ऊर्जा स्वच्छ है, पर उसके साथ दुर्घटनाओं के जोखिम हैं। इस वजह से जर्मनी ने 2023 में परमाणु विखंडन (फ़िज़न) को छोड़ने का फैसला किया है। वह भी परमाणु संलयन तकनीक पर भारी निवेश कर रहा है, जिसे वह भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखता है। जापानी नेतृत्व ने 2011 की फुकुशिमा आपदा से पैदा हुई सार्वजनिक चिंताओं के बावजूद अब परमाणु ऊर्जा को फिर से अपनी प्राथमिकता बनाया है। ईरान युद्ध ने, उनके परमाणु संयंत्रों को फिर से खोलने और नए संयंत्र बनाने की बातें हैं। दक्षिण कोरिया पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। वह भी अपनी असैनिक-परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा के सतत विकास के लिए फास्ट ब्रीडर की अनिवार्यता को डॉ. होमी भाभा ने 1950 के दशक में ही समझ लिया था। उन्होंने माना कि भारत में यूरेनियम के सीमित भंडार नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। उन्होंने यूरेनियम के कुशल उपयोग के लिए ब्रीडर प्रणाली का सुझाव दिया। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम, दीर्घकालीन परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएफबीआर परियोजना की गतिविधियां 2003 में शुरू हुईं और उसी वर्ष 'भाविनी' नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना हुई। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकैलिटी केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह भारत के दीर्घकालिक परमाणु विज़न की परिपक्वता और उसकी स्वदेशी क्षमताओं की मजबूती को दर्शाती है। सीमित यूरेनियम संसाधनों से लेकर थोरियम-संचालित भविष्य तक, भारत का तीन-चरणीय कार्यक्रम अब क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में हुई प्रगति उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों में भरोसे को दर्शाती है।

जैसे-जैसे क्षमता का विस्तार होगा और नई प्रौद्योगिकियां आकार लेंगी, परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण में कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभाने लगेगी। इस समय रूस ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) संचालित कर रहा है। हालांकि, कई देशों ने प्रायोगिक फास्ट रिएक्टर विकसित या संचालित किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और चीन शामिल हैं, पर इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम बंद हैं। इनकी लागत और तकनीकी सुरक्षा आड़े आई, पर भारत ने इन दिक्कतों पर काबू पाया है, क्योंकि यह तकनीक ही हमारी मददगार है।

भारत के पास सीमित यूरेनियम भंडार हैं, लेकिन थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इसके लिए हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने तीन-चरणों वाला नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण है, प्रेशराइज़्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर), जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम उत्पन्न करता है, जो अगले चरण के लिए मुख्य इनपुट बनता है। दूसरा चरण है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)। चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप एफबीआर इस चरण में भारत के प्रवेश का संकेत देता है। इन रिएक्टरों का उपयोग थोरियम से यूरेनियम-233 बनाने के लिए किया जाएगा, जो चरण 3 की नींव रखेगा। चरण 3 है थोरियम-आधारित रिएक्टर। इसमें भारत के विशाल थोरियम भंडार का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, जिसमें चरण 2 में उत्पन्न यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। थोरियम को व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा स्रोत माना जाता है और यह चरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है।

अभियान

पीपल की छांव का रहस्य: डर, परंपरा और विज्ञान की अनकही कहानी

गर्मियों की शांत रात, खुले आकाश के नीचे फैली चांदनी, दूर कहीं झींगुरों की आवाज़ और गांव की चौपाल पर बैठे लोग—यह दृश्य अपने आप में एक अलग ही सुकून देता है। ऐसे माहौल में पेड़ों की छांव में बैठना मानो प्रकृति की गोद में बैठने जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की बात करता है, घर की दादी-नानी तुरंत टोक देती हैं—"पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा।" बचपन में यह बात सुनकर मन में डर पैदा होता है, लेकिन जैसे-जैसे समझ बढ़ती है, यह सवाल भी उठता है कि आखिर इसके पीछे सच क्या है। क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा अनुभव और तर्क भी छिपा है?

भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ को अत्यंत पवित्र और विशेष स्थान दिया गया है। इसे केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि जीवनदायी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, और कई स्थानों पर इसे गौतम बुद्ध से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति भी एक पवित्र वृक्ष के नीचे ही हुई थी। यही कारण है कि लोग पीपल की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसे जीवन के संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। यह पेड़ हमारे समाज में श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

लेकिन जब बात रात की आती है, तो यही पवित्र वृक्ष डर और रहस्य का केंद्र बन जाता है। पुरानी लोककथाओं और मान्यताओं में यह कहा जाता रहा है कि सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दादी-नानी की कहानियों में भूत-प्रेत, आत्माएं और अदृश्य शक्तियां इसी पेड़ के आसपास घूमती दिखाई जाती थीं। यह सुनकर बच्चे डर जाते थे और स्वाभाविक रूप से रात में घर से बाहर निकलने से बचते थे। यदि गहराई से देखा जाए, तो यह डर वास्तव में सुरक्षा का एक माध्यम था। पुराने समय में जब बिजली की सुविधा नहीं थी, अंधेरा घना होता था और जंगली जीवों का खतरा भी बना रहता था, तब बच्चों और युवाओं को रात में बाहर भटकने से रोकने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गईं।

यह मान्यता केवल डर फैलाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जीवन की रक्षा का व्यावहारिक ज्ञान छिपा हुआ था। गांवों में पीपल के पेड़ अक्सर सुनसान स्थानों पर होते थे, जहां रात के समय जाना खतरनाक हो सकता था। वहां सांप, बिच्छू या अन्य जीव-जंतु हो सकते थे, जो अंधेरे में दिखाई नहीं देते। इसलिए बुजुर्गों ने इसे एक रहस्यमयी कहानी का रूप देकर समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास किया।

अब यदि इस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए, तो इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण सामने आता है। दिन के समय सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कारण है कि पेड़ों के आसपास दिन में वातावरण शुद्ध और ताजगी भरा महसूस होता है। पीपल का पेड़ विशेष रूप से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

लेकिन रात के समय स्थिति बदल जाती है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और पेड़ भी अन्य जीवों की तरह श्वसन करते हैं। इस दौरान वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि यह मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक पेड़ के नीचे बैठा रहे, विशेष रूप से घने और बड़े पेड़ के नीचे, तो उसे हल्की घुटन या असहजता महसूस हो सकती है। पुराने समय में लोग इस अनुभव को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इसे अलौकिक कारणों से जोड़ दिया।

इसके अलावा, रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे मच्छरों और कीट-पतंगों की संख्या भी अधिक होती है। ये छोटे जीव न केवल असुविधा पैदा करते हैं, बल्कि कई बार बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। गर्मियों की रातों में जब लोग खुले में सोते थे, तब इन कीटों से बचाव करना कठिन होता था। इसलिए बुजुर्गों ने यह नियम बना दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं बैठना चाहिए। यह नियम धीरे-धीरे एक परंपरा बन गया और इसके साथ डर की कहानियां भी जुड़ गईं।

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि पीपल का पेड़ बहुत पुराना और विशाल होता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं और शाखाएं दूर-दूर तक फैली होती हैं। रात के अंधेरे में जब हवा चलती है, तो इसकी पत्तियों से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यह सरसराहट कई बार डरावनी लगती है, खासकर तब जब आसपास कोई और आवाज़ न हो। पुराने समय में जब प्राकृतिक घटनाओं को समझने के साधन सीमित थे, तब ऐसी आवाज़ों को भूत-प्रेत से जोड़ दिया गया।

इस पूरी परंपरा को समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दादी-नानी की बातों में केवल अंधविश्वास नहीं था, बल्कि अनुभव, विज्ञान और सामाजिक सुरक्षा का गहरा मिश्रण था। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखा, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहानियों और मान्यताओं का सहारा लिया। यह तरीका भले ही आधुनिक दृष्टि से सरल या अंधविश्वासी लगे, लेकिन उस समय के संदर्भ में यह अत्यंत प्रभावी और उपयोगी था।

आज के समय में, जब हमारे पास विज्ञान और तकनीक की बेहतर समझ है, तब हमें इन मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर पूरी तरह नकारने के बजाय उनके पीछे छिपे तर्क को समझने की आवश्यकता है। यह समझ हमें न केवल अपने अतीत से जोड़ती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने सूझबूझ वाले थे। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय खोजे, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि पीपल का पेड़ कोई डरावनी या हानिकारक चीज़ है। इसके विपरीत, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी वृक्ष है, जो पर्यावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिन के समय इसकी छांव में बैठना, ध्यान करना या विश्राम करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह पेड़ हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसे सम्मान देने की प्रेरणा देता है।

अंततः, "पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा" जैसी बातें केवल डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि यह एक संदेश था—सुरक्षा का, सावधानी का और प्रकृति के नियमों को समझने का। जब हम इस संदेश को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे बुजुर्गों की हर बात के पीछे कोई न कोई गहरी सोच और अनुभव अवश्य होता है। इसलिए अगली बार जब कोई दादी-नानी यह बात कहें, तो उसे केवल एक कहानी समझकर अनदेखा न करें, बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान और प्रेम को भी समझने का प्रयास करें।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सूरत इकोनॉमिक रीजन 2047 तक 20 गुना वृद्धि के साथ गुजरात की जीएसडीपी में 35 फीसदी से अधिक का योगदान देगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' थीम के साथ वीजीआरसी का भव्य शुभारंभ किया

▸▸ वैश्विक युद्ध, सप्लाई चेन के संकट के बीच भी भारत अडिग : पिछले 4 वर्ष और 60 दिनों से देश में ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई : केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी

▸▸ मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात रीजन के पांच जिलों में 8 नए 'स्मार्ट जीआईडीसी' औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की

▸▸ 'सूरत कट डायमंड' को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष कवर का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

▸▸ सूरत के उद्योगों ने देश की ऐतिहासिक परियोजनाओं में आधारभूत योगदान दिया है

▸▸ दुनिया के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेल ब्रिज' और रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तोपों के निर्माण में सूरत के उद्योगों का गौरवशाली योगदान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ गुजरात ने वीजीआरसी का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया, ताकि कोई भी क्षेत्र विकास में पीछे न रह जाए, साथ ही जिले की क्षमताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म भी मिले

▸▸ समावेशी विकास की भावना के साथ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का निर्माण करने के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस परफेक्ट प्लेटफॉर्म है

▸▸ रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास का लक्ष्य रखा है

▸▸ सूरत इकोनॉमिक रीजन में केमिकल और फार्मा, टेक्सटाइल एंड अपैरल तथा जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और टूरिज्म के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं

▸▸ सूरत जल, जमीन और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाला भारत का वेल कनेक्टेड शहर बन रहा है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ राज्य सरकार गुजरात में सपने लेकर आए निवेशकों की मित्र, भागीदार और शुभचिंतक है

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत सहित दक्षिण गुजरात के विकास को मिलेगी नई ऊर्जा

▸▸ गुजरात देश की कुल जीडीपी में 8.2 फीसदी योगदान के साथ अग्रणी : राज्य की जीडीपी में दक्षिण गुजरात के योगदान को 2047 तक 20 फीसदी तक ले जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य

▸▸ औद्योगिक इंसेंटिव के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सरकार ने बनाई है पारदर्शी व्यवस्था

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सूरत में तीसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का भव्य शुभारंभ करते हुए साफ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से गुजरात ने वीजीआरसी का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि राज्य का कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए, साथ ही जिले की क्षमताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म भी मिले।

उन्होंने इससे पूर्व उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ रीजन में आयोजित दो वीजीआरसी की सफलता का संदर्भ देते हुए कहा कि समावेशी विकास की भावना के साथ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का निर्माण करने के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है।

उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण गुजरात रीजन की वीजीआरसी में सूरत सहित तापी, नवसारी, वलसाड, डांग और भरूच जिले की औद्योगिक विकास की क्षमताओं और संभावनाओं को अधिक वेग मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सूरत इकोनॉमिक रीजन में केमिकल और फार्मा, टेक्सटाइल एंड अपैरल तथा जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टटे और टूरिज्म की निहित संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने यह भी कहा कि, इस अनुमान के साथ कि सूरत इकोनॉमिक रीजन 2047 तक बीस गुना वृद्धि के साथ गुजरात की जीएसडीपी में 35 फीसदी से अधिक का योगदान देगा, नीति आयोग के मार्गदर्शन में सूरत को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान मंजूर भी हो गया है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, नेशनल हाईवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, पोर्ट, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल और आउटर रिंग रोड आदि से जुड़कर हवाई, जल और जमीनी कनेक्टिविटी के माध्यम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाला भारत का वेल-कनेक्टेड शहर बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू हुई दक्षिण गुजरात क्षेत्र की इस वीजीआरसी को प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में 2001 के बाद हुए आमूल बदलाव और विकास के नए मील के पत्थर का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में बंदरगाह-आधारित विकास सहित हुए निरंतर अप्रतिम विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज गुजरात अकेला देश के कुल कार्गो का 40 फीसदी हैंडलिंग करता है। इतना ही नहीं, गुजरात औद्योगिक उत्पादन (इंडस्ट्रियल आउटपुट) में 18 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा में 15 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 9 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अलावा, गुजरात ने इन ढाई दशकों में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। साणंद और धोलेरा सेमीकंडक्टर हब बन गए हैं। अब तक दो सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट और प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट विजन के परिणामस्वरूप गुजरात आज देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य का प्रत्येक जिला अपनी विशिष्ट संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए करीब 20 प्रायोरिटी सेक्टर्स के साथ छह रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित गुजरात 2047 का रोडमैप तैयार किया है। इसमें अर्निंग वेल, लिविंग वेल के ध्येय के साथ 2047 का गुजरात कैसा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, ईवी, ग्रीन हाईड्रोजन, और एआई जैसी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के जरिए इन्वेस्टमेंट एंड एंप्लॉयमेंट, दोनों को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात की इस वीजीआरसी में सहभागी हो रहे उद्योग-व्यापार जगत के दिग्गजों से विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात रीजन में सूरत जिले में 2, भरूच में 3, वलसाड में 1, तापी में 1 और नवसारी जिले में 1 सहित कुल 5380 एकड़ में आकार लेने वाले 8 नए 'स्मार्ट जीआईडीसी' औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सभी नागरिकों को गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के आयोजन से सूरत और दक्षिण गुजरात के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। वाइब्रेंट गुजरात को क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अब राज्य के चार जोन में रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं।

श्री संघवी ने वाइब्रेंट गुजरात की दो दशकों की सफलता के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए जोड़ा कि वर्ष 2003 में गुजरात की जीडीपी 1.29 लाख करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7.20 लाख करोड़ रुपए हो गई। प्रगति की इस यात्रा को जारी रखते हुए वर्ष 2022-23 में जीडीपी 21.90 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2025 के अंत तक 27.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। गुजरात आज देश की कुल जीडीपी में 8.2 प्रतिशत योगदान के साथ देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने इस विकास यात्रा में उद्योगपतियों के अमूल्य योगदान की सराहना की।

राज्य की औद्योगिक क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए श्री संघवी ने कहा कि राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) में गुजरात पूरे देश में अग्रणी रहा है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन परियोजना के साकार होने से राज्य में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उद्योगपतियों के लिए नीतिगत सरलता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन सहायता (इंसेंटिव) प्राप्त करने के लिए अब उद्योगपतियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 5,619 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का वितरण किया गया है, जिसके अंतर्गत कल ही सूरत से 11,000 व्यापारियों को 1,300 करोड़ रुपए की सहायता सीधे प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुजरात में सपने लेकर आने वाले निवेशकों की मित्र, भागीदार और शुभचिंतक है। उन्होंने मेहसाणा वीजीआरसी में हुए 3.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और राजकोट में हुए 5.78 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का जिक्र करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि सूरत में भी रिकॉर्ड संख्या में एमओयू होंगे। प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के जिलों को शामिल करते हुए 'सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान @2047' तैयार किया है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी में दक्षिण गुजरात की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है।

दक्षिण गुजरात की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री संघवी ने कहा कि देश के 60 प्रतिशत सोलर पैनल और सोलर सेल का उत्पादन इस क्षेत्र में हो रहा है। कुशल मानवबल और पोर्ट कनेक्टिविटी के कारण लॉजिस्टिक्स लागत भी बहुत कम आती है। सूरत आज देश के 75 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन और निर्यात करता है तथा विश्व के हर 100 में से 90 हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। स्वच्छता में भी सूरत देश में प्रथम स्थान पर होने का गौरव व्यक्त करते हुए उन्होंने उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्ष 2027 के वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले इस प्रकार की क्षेत्रीय समिट के आयोजन के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समिट अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श और प्रेरणादायक बनी है। वैश्विक स्तर पर बीमा लागत में वृद्धि, कार्गो में देरी और सप्लाई चेन की गंभीर समस्याओं के बीच भी भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में सुरक्षित रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला संकट और हॉर्मुज की खाड़ी में उत्पन्न तनाव के बावजूद केंद्र सरकार ने देशवासियों को आर्थिक बोझ से बचाया है।

इस संदर्भ में श्री पुरी ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी वृद्धि हुई है, तब भी पिछले 4 वर्ष और 60 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने पड़ोसी देशों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश में अप्रैल महीने में पेट्रोल के दामों में 42.7 प्रतिशत और डीजल में 54.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण के पड़ोसी देशों में भी ईंधन के दामों में 39 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य बाजारों में लंबी कतारें, राशनिंग और काम के घंटों में कटौती जैसी स्थिति देखने को मिली है, लेकिन भारत ने 'पैनिक' (घबराहट) को कभी अपनी नीति नहीं बनने दिया। भारतीय रसोई में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी गई।

श्री पुरी ने आगे जोड़ा कि कई लोग देश में कीमतों की स्थिरता को चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 4 वर्षों में कई चुनाव आए और गए, फिर भी सरकार की प्रतिबद्धता आम जनता को राहत देने की रही है। सरकार ग्राहकों के हित में कठोर निर्णय लेने में सक्षम है और भविष्य में भी जनहित सर्वोपरि रहेगा।

गुजरात गौरव दिवस के पावन अवसर पर दक्षिण जोन की 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' की पहली बार मेजबानी करने के लिए सूरतवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुई 'वाइब्रेंट गुजरात' समिट की सफलता के कारण आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं।

सूरत के उद्योगों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री पाटिल ने गौरवपूर्वक कहा कि जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेल ब्रिज' में सूरत की एम/एनएस इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित अत्यंत मजबूत स्टील का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हजीरा स्थित एलएंडटी प्लांट में तैयार की गई आधुनिक तोपें (के9 वज्र) देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यह केवल सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए गौरव का क्षण है।

उन्होंने जोड़ा कि देश में पानी की जरुरतों को पूरा करने के लिए जल संचय के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जागरूक देशवासियों ने जनभागीदारी से 70 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे 2 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) अतिरिक्त जल संचय संभव हुआ है। आज 83 प्रतिशत पानी कृषि में उपयोग होता है, जबकि 14 प्रतिशत पानी जनसमुदायों में तथा 2.5 प्रतिशत पानी उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से भूजल का अनावश्यक दोहन न करने और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाते हुए जल संरक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि महानगर पालिका द्वारा टर्शियरी ट्रीटेड वॉटर बेचकर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त की जा रही है और सूरत ने आने वाले 50 वर्षों की जल आवश्यकता के लिए ठोस और भविष्योन्मुखी योजना तैयार की है।

उन्होंने आगे कहा कि सूरत के उद्यमी एवं उनकी कार्यक्षमता के कारण ही आज बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स में सूरत की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी समय में इस रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दक्षिण गुजरात के विकास को नई गति मिलेगी।

भारत स्थित जापान के राजदूत श्री ओनो केइची ने अपने संबोधन की शुरुआत गुजराती भाषा करते हुए कहा, "2009 में जापान पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट के भागीदार देश के रूप में जुड़ा। तब से हम लगातार गुजरात की पार्टनर कंट्री रहे हैं। उसका हमें बहुत गौरव है।" उन्होंने कहा कि सूरत भारत के अग्रणी व्यापारिक शहरों में एक है तथा डायमंड प्रोसेसिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में बहुत ही विख्यात बना है। जापान-भारत के संबंधों के संदर्भ में हाईस्पीड रेलवे ट्रेन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण हब के रूप में भी सूरत का बहुत महत्व है।

उन्होंने कहा, "सूरत जैसे महत्वपूर्ण शहर में इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन बहुत उल्लेखनीय है। सूरत तथा गुजरात राज्य के अधिक समृद्ध आर्थिक विकास के लिए जापान सदा समर्थन देता रहेगा।"

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हजीरा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के स्टील प्लांट में कुल निवेश 1.4 ट्रिलियन रुपए है तथा उसके जरिये लगभग 40 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। अब तक इस प्लांट द्वारा 7.2 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ है और उसे निकट भविष्य में 15 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा।

सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सरकार तथा निजी कंपनियों के बीच का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जापान भी भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने के देश के सपने को साकार करने में और विशेषकर गुजरात राज्य में उसका उत्पादन करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट में सूरत एक मेजर हब है तथा जापान सरकार उसका मजबूती से समर्थन कर रही है। निकट भविष्य में इस शहर में आकार ले रहे जापान-इंडिया जॉइंट प्रोजेक्ट के ठोस परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मारुति-सुजुकी गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के एक प्लांट के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। यह पहल पर्यावरण पर प्रभाव ही कम नहीं करती है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ाती है और किसानों के लिए आजीविका बढ़ाने में भी योगदान देती है।

उन्होंने कहा, "गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के कारण दोनों देशों के बीच इस विशेष रणनीतिक वैश्विक भागीदारी ने एक नए युग के स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश किया है। आगामी 2027 का वर्ष जापान तथा भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं 2027 को विशेष वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा व्यापारी समुदायों के साथ मिलकर केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि भारत के कई भागों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहता हूं। 75वें वर्ष को वास्तव में अविस्मरणीय तथा विशेष बनाने के लिए मैं गुजरात राज्य के साथ काम करने को आतुर हूं।" उन्होंने गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।

सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वोंग ने सभी का 'जय श्री कृष्ण' के साथ अभिवादन करते हुए कहा कि आज का दिन महान है, जब रीजनल कॉन्फ्रेंस के दिन अन्य तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ भी जुड़ी हैं। आज गुजरात का स्थापना दिवस भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और विश्व में लेबर डे भी मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रूप से उच्च स्तर पर गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत में सिंगापुर की ओर से सर्वाधिक एफडीआई दर्ज कराया गया है। वर्ष 2014 से अब तक भारत में क्युमुलेटिव एफडीआई 179 बिलियन डॉलर है। जहां तक गुजरात की बात है, तो भारत से सिंगापुर होने वाले निर्यात में 15 प्रतिशत गुजरात से आता है।

उन्होंने कहा कि आज यह कॉन्फ्रेंस सूरत में है। 100 मिलियन डॉलर मूल्य के हीरे सूरत से सिंगापुर एक्सपोर्ट होते हैं। हर चार में से एक डेनिम जींस सूरत से आता है।

उन्होंने कहा, "हम धोलेरा, गिफ्ट सिटी तथा साणंद में सेमीकंडक्टर तथा फाइनेंस क्षेत्र में आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने निरंतर सिंगापुर की यात्राएं कीं। इस कारण यह संबंध दीर्घकालीन है। आगामी वाइब्रेंट गुजरात की मुख्य इवेंट में सिंगापुर अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगा।

इस अवसर पर सूरत तथा गुजरात के हीरा उद्योग के लिए गौरव समान 'सूरत कट डायमंड' को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक द्वारा जारी एक विशेष कवर का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया गया।

इस मौके पर उपस्थित सभी ने 'वाइब्रेंट गुजरात तथा विकसित गुजरात' की थीम के साथ राज्य के विकास का विजन प्रस्तुत करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म रुचिपूर्वक देखी।

इस अवसर पर निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर श्री नोबुओ ओकोची, एसोचैम के अध्यक्ष श्री निर्मल मिंडा, रवांडा की उच्चायुक्त श्री जैक्लीन मुकानगीरा, यूक्रेन के उच्चायुक्त ओलेक्सांद्र पोलिशचुक, राज्य सरकार के मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, जीतूभाई वाघाणी, ऋषिकेशभाई पटेल, प्रद्युमनभाई वाजा, नरेशभाई पटेल, रमणभाई सोलंकी, डॉ. जयरामभाई गामित, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायक, राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, अपर मुख्य सचिव श्री जयंती रवि, उद्योग सचिव श्री ममता वर्मा, निर्वाचित वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण गुजरात के डायमंड, टेक्सटाइल आदि क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी, युवा उद्यमी, विदेशी उद्योगकार आदि उपस्थित रहे।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सूरत में 'नारी शक्ति वंदन' सेमिनार आयोजित

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्र निर्माण के स्तंभ के रूप में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया, सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की

▸▸ महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सशक्त परिवार और विकसित भारत की ओर : डॉ. जयंती रवि, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन शुक्रवार को सूरत में 'शक्ति संगम : गुजरात विकसित भारत के विकास इंजन के रूप में' विषयवस्तु पर 'नारी शक्ति वंदन' सेमिनार आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा रवांडा की भारत स्थित उच्चायुक्त सुश्री जैकलिन मुकांगिरा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति का स्रोत माना जाता है और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि विधानसभाओं और लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे नेतृत्व, निर्णय-प्रक्रिया और राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने कहा कि देश महिलाओं के विकास से हटकर अब 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति बन रही हैं।

उन्होंने कन्या केळवणी अभियान के सफल कार्यान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख किया और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की जरूरत पर बल दिया।

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग की अध्यक्ष सुश्री अंकिता वालंदे ने कहा कि यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात को वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उन्होंने टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्युटिकल्स और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के योगदान को रेखांकित किया।

सेमिनार के दौरान 'शक्ति संगम' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में सुरक्षा, समाज सेवा, उद्यमशीलता और शासन में महिलाओं की भूमिका पर व्यापक मंथन किया गया। दूसरी पैनल चर्चा में 'सूरत में नारी शक्ति : विकसित सूरत से विकसित भारत' विषय के अंतर्गत एआई, डिजिटल इकोसिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला गया।

इन स्तंभों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से महिलाएं केवल अपनी स्वयं की प्रगति ही सुनिश्चित नहीं कर रही हैं, बल्कि सुदृढ़ परिवारों, सशक्त समाजों तथा प्रगतिशील एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र को प्रोत्साहन देकर 'विकसित भारत@2047' के विजन को भी गति दे रही हैं।

पैनल में गुजरात कैडर की आईपीएस सूरत साइबर क्राइम की उपायुक्त श्रीमती बिशाखा जैन, गेट्स फाउंडेशन की इंडिया कंट्री डायरेक्टर सुश्री अर्चना व्यास, उपासना की संस्थापक सुश्री उमा प्रजापति, 'सखी' एवं ऑरोविल की संस्थापक एवं सीईओ सुश्री देवी नमसिवयम, साधना फॉरेस्ट की सह-संस्थापक सुश्री योरित रोजिन और एसोचैम की हेड-स्टेट्स (ऑल इंडिया) सुश्री परमिंदर जीत कौर सहित अनेक महानुभाव उपस्थित रहे।

सत्र में प्रधानमंत्री के 5एफ फॉर्मूला का उल्लेख किया गया, जो फार्म (खेत) से लेकर फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से फॉरेन (विदेश) तक कपड़े की मूल्य शृंखला को मजबूत करने का एक व्यापक विजन प्रस्तुत करता है।

सत्र में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास को समावेशी शहरी विकास की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में रेखांकित किया गया, जिसमें महिलाओं को सृजनकर्ता, नेता और निर्णयकर्ता के रूप में विशेष महत्व दिया गया। इसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार एआई और डिजिटल इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी परिवारों को मजबूत कर रही है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और सूरत को विकसित भारत की ओर अग्रसर कर रही है।

इस अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया गया। इसके अलावा, उद्योग एवं खान विभाग और जिनाश गारमेंट के बीच 6 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत सूरत और नवसारी जिले में लगभग 1000 महिलाओं को रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों की औसत मासिक आय लगभग 11,000 होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। पूरे सेमिनार ने महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखने की दिशा में मजबूत संदेश दिया।

रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने फ़िर से रचे शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान

मुंबई। मुंबई के प्रमुख शिक्षा संस्थान रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आईसीएसई परीक्षा में अपने विद्यार्थियों की असाधारण उपलब्धियों की बदौलत शैक्षणिक उत्कृष्टता के नये प्रतिमान रचते हुए एक बार फ़िर से शानदार सफलता का परचम लहराया है।

यह जानकारी देते हुए रायन इंटरनेशनल स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका तथा मुंबई की सुपरिचित साहित्यकार श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रायन इंटर नेशनल स्कूल, चेम्बूर का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में समारोहपूर्वक ख़ुशियाँ मनाईं गईं। उन्होंने बताया कि रायन इंटरनेशनल स्कूल, चेंबूर ने हाल ही में हुई परीक्षाओं में 100% रिज़ल्ट पाकर गर्व महसूस किया है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के उसके सफ़र में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि यह शानदार उपलब्धि स्कूल के होलिस्टिक एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड लर्निंग और लगातार एकेडमिक सपोर्ट के लिए पक्के कमिटमेंट को दिखाती है। मेधावी और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के इस ग्रुप को लीड करते हुए अनन्या श्रीकांत ने शानदार 99.40% हासिल किये। उसके बाद स्वरा प्रशांत शिंदे ने 98.60% अंक प्राप्त किये। उन्होंने कहा कि स्कूल को ऋषभ बनर्जी, कविश अमित परमार और मानित हेमल गांधी के शानदार परफॉर्मेंस पर भी बहुत गर्व है, जिन्होंने 97 % अंक स्कोर करके खुद को टॉप अचीवर्स में शामिल किया है। यह ओवर ऑल रिज़ल्ट एनालिसिस स्कूल के मज़बूत एकेडमिक परफॉर्मेंस को बखूबी दिखाता है। उन्होंने बताया कि कुल 14 स्टूडेंट्स ने 95% से ज़्यादा स्कोर किया, जबकि 64 स्टूडेंट्स ने 85% और 94% के बीच स्कोर किया। इसके अलावा, 48 स्टूडेंट्स ने 75% से 84% तक मार्क्स हासिल किए, और 15 स्टूडेंट्स ने 60% से 74% के बीच स्कोर किया। खास बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने 60% से कम स्कोर नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशन के लगातार बेहतरीन एकेडमिक स्टैंडर्ड को दर्शाता है। एग्जाम देने वाले कुल स्टूडेंट्स की

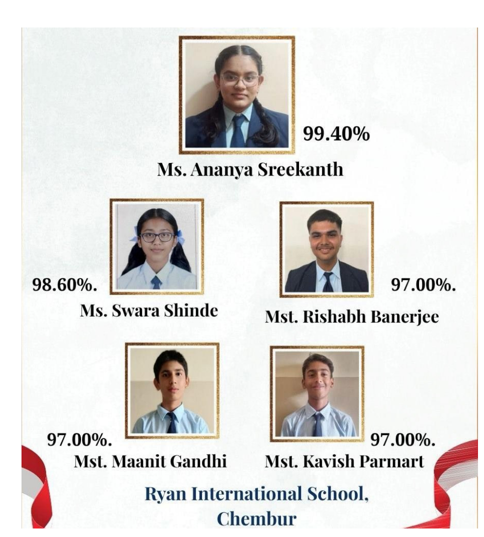

संख्या 141 थी। उन्होंने कहा कि यह शानदार कामयाबी स्टूडेंट्स की लगन और कड़ी मेहनत का पुख़्ता सबूत है। साथ ही यह स्कूल की बहुत ही समर्पित फैकल्टी की लगातार कोशिशों को भी दिखाता है, जिनके गाइडेंस और मेंटरशिप ने इन सफलताओं को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि माता- पिता से लगातार हिम्मत और सपोर्ट ने इस कामयाबी को और मज़बूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र-छात्राओं की सफलता हमारी सम्माननीय प्रबंधन टीम के अथक प्रयासों और समर्पण का भी प्रमाण है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को पोषित करने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए अध्यक्ष डॉ. ए. एफ. पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो का योगदान अतुलनीय रहा है। विद्यालय के चेयरमैन ने सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि चेंबूर के रायन इंटरनेशनल स्कूल में, हम युवा दिमागों को न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज़ में भी बेहतरीन बनाने में यकीन रखते हैं।

सूरत में "गौ सम्मान अभियान" को लेकर व्यापारी एकजुट, 7 मई को विशाल रैली का ऐलान

सूरत में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर एक बार फिर व्यापारी समुदाय सक्रिय नजर आ रहा है। "गौ सम्मान अभियान" के समर्थन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शहर के प्रमुख व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों ने इस पहल को केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और परंपराओं से जुड़ा दायित्व बताया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति में गौमाता का स्थान अत्यंत पूजनीय रहा है। इसी भावना को मजबूत करते हुए अभियान का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की मांग को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और सूरत जैसे बड़े व्यापारिक शहर में इसे जनआंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। व्यापारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभियान को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जनसहभागिता से जोड़ते हुए बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत निर्धारित फॉर्म के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य समाज की भावनाओं को संगठित और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि इसे शासन-प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जा सके। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 7 मई 2026 को एक विशाल रैली आयोजित करने का लिया गया। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली इस रैली में व्यापारी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आयोजकों का मानना है कि यह रैली अभियान को नई गति देगी और शहर में एक व्यापक जनसमर्थन का प्रदर्शन करेगी। रैली के बाद एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा जाएगा, जिससे इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। इस अभियान को लेकर शहर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को डुंभाल बालाजी मंदिर में साध्वी कपिलाश्री के सानिध्य में एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान की रूपरेखा को और स्पष्ट किया गया तथा विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गईं। इस बैठक में भी बड़ी संख्या में व्यापारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आश्वासन दिया।

श्रमिकों के सम्मान में सूरत में आध्यात्मिक संगम: ब्रह्माकुमारीज़ का प्रेरक आयोजन

सूरत में ब्रह्माकुमारीज़ की वराछा स्थित शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर एक भावपूर्ण और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूरत नगर निगम से जुड़े श्रमिक भाई-बहनों का सम्मान किया गया। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि श्रम के महत्व, सेवा की भावना और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम बनकर सामने आया, जिसने उपस्थित सभी लोगों के मन को गहराई से स्पर्श किया।

कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की स्मृति के साथ हुई, जिससे पूरे वातावरण में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही दीप प्रज्वलन हुआ, कार्यक्रम ने एक पवित्र और गरिमामय स्वरूप धारण कर लिया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी तृप्तिबेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया। उनके साथ कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, जो लोक दृष्टि आई बैंक और रेड क्रॉस ब्लड सेंटर से जुड़े हैं, सेनेटरी इंस्पेक्टर अकबरी भाई, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक निलेशभाई, डॉ. विनोदभाई तथा शहर के अग्रणी व्यवसायी किशोरभाई भी मंच पर विराजमान रहे। अपने प्रेरक संबोधन में तृप्तिबेन ने श्रमिकों को समाज की प्रगति का वास्तविक आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि उनका योगदान केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज की आत्मा को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने श्रम को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक सेवा और साधना के रूप में देखने की प्रेरणा दी। उनके शब्दों में गहराई और सादगी दोनों थीं, जो सीधे श्रमिकों के दिल तक पहुंचीं। उन्होंने यह भी कहा कि परिश्रम से अर्जित आय केवल आर्थिक स्थिरता नहीं देती, बल्कि परिवार में सुख, शांति और संतोष का वातावरण भी निर्मित करती है। साथ ही उन्होंने सभी को व्यसनमुक्त जीवन अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि सच्ची खुशहाली भीतर की शुद्धता और संयम से आती है। डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने भी अपने संबोधन में श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता और सुव्यवस्था के पीछे सफाई कर्मियों की अथक मेहनत होती है। उन्होंने

इस बात पर जोर दिया कि यदि श्रमिक स्वयं भी अपने जीवन में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, तो वे न केवल समाज को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व मेयर अस्मिताबेन शिरोया की ओर से भी सूरत को स्वच्छता में अग्रणी स्थान दिलाने में श्रमिकों की भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन ब्रह्माकुमारी साक्षीबेन ने किया, जिन्होंने श्रमिकों को परमात्मा के सच्चे सहयोगी बताते हुए कहा कि समाज की संरचना में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों ने श्रमिकों के मन में आत्मगौरव और सम्मान की भावना को और मजबूत किया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्माकुमारी अनीषाबेन, कृपालीबेन और सोनलबेन ने भी प्रेरणादायक नारों और दृढ़ संकल्पों के माध्यम से सभी को सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण वह था जब लगभग 200 श्रमिक भाई-बहनों का सम्मान किया गया। उन्हें तिलक, पुष्प, ब्लेसिंग कार्ड और ईश्वरीय भेंट देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उनके योगदान के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक था। मंचासीन सभी अतिथियों को भी ईश्वरीय स्मृति-चिन्ह और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई।

कार्यक्रम के अंत में ब्रह्माकुमारी सोनलबेन ने सभी अतिथियों, आयोजकों और उपस्थित श्रमिकों का आभार व्यक्त किया। उनके धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही यह आयोजन अपने समापन की ओर बढ़ा, लेकिन इसके संदेश और भावनाएं उपस्थित लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहने वाली थीं। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने प्रभु प्रसाद ग्रहण किया, जिससे एकता और सामूहिकता की भावना और भी प्रबल हुई।

यह आयोजन केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि समाज के हर वर्ग का सम्मान और सराहना जरूरी है, खासकर उन लोगों की, जो चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्माकुमारीज़ का यह प्रयास न केवल श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला रहा, बल्कि इसने समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सम्मान और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया। ऐसे आयोजन यह याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति तभी संभव है, जब हर व्यक्ति को उसके योगदान के लिए सम्मान मिले और उसे समाज में समान स्थान दिया जाए।

भावनगर मंडल द्वारा सघन टिकट जांच अभियान में उल्लेखनीय सफलता, अप्रैल 2026 में 91.32 लाख का राजस्व अर्जित

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अप्रैल 2026 के दौरान चलाए गए सघन टिकट जांच अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस अवधि में कुल 11,943 यात्री अनियमित यात्रा करते हुए पाए गए, जिनमें से 5,283 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए। इन सघन जांच कार्रवाइयों से मंडल ने अप्रैल माह में 91.32 लाख का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के अप्रैल माह के 77.22 लाख की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। यह पिछले दो वर्षों में किसी एक माह के दौरान टिकट जाँच की अधिकतम आय है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह उत्कृष्ट प्रदर्शन मंडल की प्रभावी निगरानी व्यवस्था, सतत जांच अभियानों तथा यात्री सेवाओं के सुव्यवस्थित प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के समग्र प्रदर्शन की बात करें तो भावनगर मंडल ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 1345.63 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है।

टिकट जांच अभियान के अंतर्गत भी वर्ष 2025–26 में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की गई। इस अवधि में टिकट जांच से 7.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.8% अधिक होने के साथ-साथ अब तक का सर्वाधिक है। यह उपलब्धि टिकट जांच स्टाफ की सतर्कता, नियमितता एवं सघन निरीक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर सभी संबंधित कर्मचारियों की सराहना की है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सघन टिकट जांच अभियान चलाकर राजस्व वृद्धि एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का संकल्प दोहराया है।

पश्चिम रेलवे का राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच मेजर ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों के लॉन्चिंग कार्य के लिए उपनगरीय खंड पर शनिवार/रविवार, अर्थात 2/3 मई, 2026 की मध्यरात्रि को राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

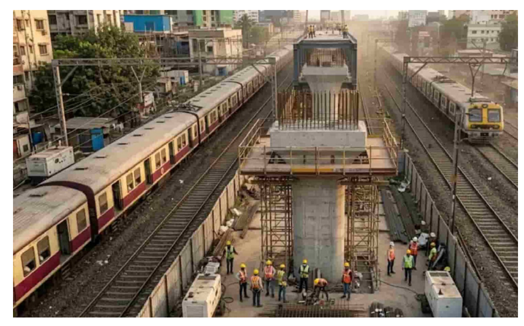

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक छठी लाइन पर 2 मई, 2026 को 21:30 बजे से 3 मई, 2026 को 07:30 बजे तक कुल 10 घंटे के लिए लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अप फास्ट लाइन तथा पाँचवी लाइन पर 01:00 बजे से 04:00 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान छठी लाइन की सभी ट्रेनें बोरीवली और अंधेरी के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएँगी तथा कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय सेवाएँ निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सभी उपनगरीय स्टेशनों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस सूरत और बोरीवली के बीच लगभग 30 मिनट रेगुलेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

Beat The Heat पहल, यात्रियों ने कहा थैंक्यू

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा इस समर सीजन में गर्मी से राहत के लिए "Beat the Heat" पहल शुरू की गई है। यात्रियों ने वडोदरा मंडल की इस पहल की विशेष सराहना की है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार ने इस पहल के बारे में बताया कि पिछले वर्ष में इस अभियान की सफ़लता के बाद इस वर्ष भी वडोदरा मंडल यात्रियों की सेवा में Beat The Heat 2.0 के जरिए उपलब्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान सामान्य श्रेणी के यात्रियों के आराम और कल्याण पर विशेष ध्यान देना था।

अभियान के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में कर्मचारियों तथा एनजीओ टीमों के सक्रिय समन्वय से इलेक्ट्रोलाइट युक्त संतरे का जूस, पेयजल और अन्य हाइड्रेशन सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इस प्रयास से विशेष रूप से अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिली।

उनके अनुसार इस पहल को गर्मी के सीज़न में लगातार 30 दिनों तक सफलतापूर्वक जारी रखा जायेगा।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, सूरत

सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा एग्जीबिशन का उद्घाटन

▶▶ ऑरो यूनिवर्सिटी में औद्योगिक विकास, ग्रीन एनर्जी, कृषि और सेवा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्रतिबिंबित करती विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन

▶▶ मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ से पूर्व ऑरो यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन का विधिवत् उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि प्रगति, ग्रीन एनर्जी और सेवा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्रतिबिंबित करती हुई एक विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के विभिन्न पवेलियन और स्टॉलों का दौरा कर उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी इकाइयों, कृषि में आधुनिक पद्धतियों और सेवा क्षेत्र के विकसित हो रहे मॉडलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने राज्य के विकास में निजी क्षेत्र, उद्योगपतियों और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रोत्साहित किया।

गुजरात देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में आगे बढ़ रहा है, तब राज्य सरकार द्वारा 'वाइब्रेंट गुजरात' के वैश्विक विजन को अधिक व्यापक बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का नूतन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस पहल के माध्यम से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सूरत में आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दक्षिण गुजरात के सूरत सहित 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें उद्योग, कृषि, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य रीजनल इन्डस्ट्री ग्रोथ को गति देना, निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। इस प्रदर्शनी को औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और सेवा क्षेत्र जैसे मुख्य विभागों में विभाजित किया गया है। इस प्रदर्शनी में नई उत्पादों, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, स्टार्टअप इनोवेशन और सरकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया गया है।

विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी से संबंधित परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके अलावा, गुजरात की पहचान को दर्शाने वाला 'मैंगो फेस्टिवल' भी आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण गुजरात में उगाई जाने वाली आम की विभिन्न किस्मों को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ट्रेड फेयर का भी शुभारंभ किया और प्रदर्शनी से उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक संभावनाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस प्रकार की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस राज्य के संतुलित और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर पाटिल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, विधायक, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के अग्रणी तथा देश-विदेश के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच चलाएगी तीन स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराए पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें एक पूर्णतः अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09079/09080 मुंबई सेंट्रल – इंदौर एसी सुपरफास्ट स्पेशल (द्वि-साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09079 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:00 बजे इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 मई, 2026 से 28 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09080 इंदौर–मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 04 मई, 2026 से 29 जून, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम एवं उज्जैन स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09081/09082 मुंबई सेंट्रल – वटवा एसी सुपरफास्ट स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09081 मुंबई सेंट्रल – वटवा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:20 बजे वटवा पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 मई, 2026 से 25 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09082 वटवा – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 22:40 बजे वटवा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 08 मई, 2026 से 26 जून, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर – बोरीवली पूर्णतः अनारक्षित स्पेशल

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर स्पेशल रविवार, 03 मई, 2026 को 00:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल सोमवार, 04 मई, 2026 को 20:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और बुधवार को 11:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती एवं खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या 09157 का बोरीवली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09079 एवं 09080 की बुकिंग 02.05.2026 से तथा ट्रेन संख्या 09081 एवं 09082 की बुकिंग 03.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मण्डल पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन WRWWO-अहमदाबाद द्वारा 30 रेलकर्मी सम्मानित

दिनांक 1 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO), अहमदाबाद मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न विभागों के 30 रेलकर्मियों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं उनके कठोर परिश्रम, लगन एवं निष्ठा पूर्ण कार्यों की सराहना की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर WRWWO अहमदाबाद मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शेफाली गुप्ता ने सभी रेलकर्मियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय रेल, जो देश की जीवन रेखा है, उसकी मजबूती और सफलता के पीछे लाखों कर्मचारियों का अथक परिश्रम निहित है। उन्होंने कहा कि ट्रैकमैन, गार्ड, लोको पायलट, तकनीकी कर्मचारी या स्टेशन स्टाफ—हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाता है। मजदूर दिवस हमें यह संदेश देता है कि हर श्रमिक का योगदान अमूल्य है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अपने संबोधन में रेलकर्मियों की लगन एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारी हर मौसम में बिना थके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल केवल पटरियों और ट्रेनों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। दिन-रात, गर्मी-बरसात हर परिस्थिति में रेलकर्मी अपनी सेवाएं देकर देश की गति को बनाए रखते हैं।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ सहित अन्य अधिकारीगण, महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, रेलवे यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

सूरत की सियासत में नई हलचल: महिला मेयर के चयन को लेकर भाजपा में तेज हुई 'सेंस' कवायद

सूरत नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब शहर के नए नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। 115 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ लगातार सातवीं बार सत्ता में लौटी भाजपा के सामने अब सबसे अहम सवाल यही है कि शहर का अगला मेयर कौन होगा। गजट जारी होने के साथ ही नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत होगी और इसके साथ सूरत को एक नई महिला मेयर मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार यह पद महिला (जनरल) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

यह आरक्षण अपने आप में राजनीतिक समीकरणों को बदल देने वाला साबित हो रहा है। सूरत नगर निगम के इतिहास में यह छठी बार होगा जब कोई महिला मेयर पद संभालेगी। खास बात यह है कि इस बार चुनाव में भाजपा की 58 महिला पार्षद जीतकर आई हैं, जिससे दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है और प्रतिस्पर्धा बेहद रोचक हो गई है। पार्टी के भीतर कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें अनुभवी पार्षदों से लेकर नए चेहरों तक की दावेदारी देखी जा रही है। यही वजह है कि इस बार मेयर का चयन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहन विचार-विमर्श और रणनीतिक संतुलन का परिणाम होगा।

भाजपा ने इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलित बनाने के लिए अपनी पारंपरिक 'सेंस प्रक्रिया' को अपनाया है। यह प्रक्रिया 2 मई 2026 को सुबह 10 बजे उधना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की जा रही है। इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक और शहर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। वे सभी चुने हुए पार्षदों और प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से राय लेकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच किस नाम पर सबसे अधिक सहमति बन रही है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नामों की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखना भी है। भाजपा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह इतने बड़े जनादेश के बाद भी आंतरिक असंतोष को जन्म न दे। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मेयर का चयन ऐसा हो जो सभी गुटों को संतुष्ट कर सके और शहर के विकास एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा सके। सूरत जैसे तेजी से विकसित होते शहर में मेयर की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि वह शहर की प्रशासनिक दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'सेंस प्रक्रिया' के बाद पार्टी एक पैनल तैयार करेगी, जिसमें संभावित नामों को शामिल किया जाएगा। इसी पैनल के आधार पर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, रूलिंग पार्टी लीडर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह पूरा ढांचा सूरत नगर निगम के अगले पांच वर्षों के प्रशासनिक ढांचे को निर्धारित करेगा। इसलिए हर पद पर सही व्यक्ति का चयन पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार महिला नेतृत्व को लेकर भाजपा एक मजबूत संदेश देना चाहती है। सूरत जैसे औद्योगिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में महिला मेयर का चयन न केवल सामाजिक संतुलन को दर्शाएगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि पार्टी महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे को गंभीरता से लागू कर रही है। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती है, जो प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ जनसंपर्क में भी मजबूत हो। भाजपा के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने विकास मॉडल को बनाए रखे। सूरत को देश के सबसे तेज़ी से विकसित होते शहरों में गिना जाता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और उद्योग के क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है। ऐसे में नया मेयर इस विकास की गति को बनाए रखने और नई योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। पार्टी यह भी ध्यान रख रही है कि चयनित उम्मीदवार में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता हो।

दूसरी ओर, पार्टी के भीतर चल रही यह प्रतिस्पर्धा यह भी दर्शाती है कि भाजपा के पास नेतृत्व के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, यही स्थिति कभी-कभी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि हर दावेदार अपने समर्थन के साथ आता है और उसे संतुष्ट करना आसान नहीं होता। ऐसे में 'सेंस प्रक्रिया' के जरिए पार्टी एक संतुलित और सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

आने वाले कुछ दिन सूरत की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मेयर के नाम की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वह शहर के विकास के लिए किस प्रकार का नेतृत्व चुन रही है। फिलहाल, सभी की निगाहें इस प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस महिला नेता को सूरत की कमान सौंपी जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ है कि चुनाव जीतना एक चरण होता है, लेकिन उस जीत को सही दिशा देना असली चुनौती होती है। भाजपा के लिए सूरत में यह वही क्षण है, जहां उसे अपने संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक समझ का प्रदर्शन करना है, ताकि आने वाले पांच वर्षों में शहर की प्रगति और जनता का विश्वास दोनों बरकरार रह सकें।